जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर
Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 341 प्रभात उदयपुर, रविवार 12 अक्टूबर, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

यूक्रेन युद्ध के बाद से केवल चीन की उड़ानों को रूस की एयर स्पेस लांघने का अधिकार था

इस सुविधा से चीन की व्यावसायिक उड़ानें पाश्चात्य देशों की उड़ानों से लगातार सस्ती होती जा रही थीं

- चीन की एयरलाइन्स को मिल रहे इस अनुचित लाभ को खत्म करने के लिए पाश्चात्य देशों की एयरलाइन्स ने ट्रंप को आगे किया है।
- ट्रंप अब चीन की उन उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं जो रूस की एयर स्पेस को लाँघकर अमेरिका में उतरती हैं।
- उधर चीन ने वहाँ से अमेरिका को निर्यात होने वाले रेयर अर्थ के खनिज एक्सोर्ट पर प्रतिबंध और कड़े किये। अमेरिका ने इसके प्रत्युत्तर में चीन से अमेरिका निर्यात होने वाले सामान पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी। यह व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता कहाँ जाकर रूकेगी, क्या देर सवेर सशस्त्र युद्ध में परिवर्तित होगी?

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। जहाँ एक ओर डॉनल्ड ट्रंप गाज़ा और यूक्रेन में युद्ध की आग को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं वे वैश्विक व्यापार में नए टकराव के मोर्चे खोल रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने अब रूसी हवाई क्षेत्र से होकर उड़ने वाली एयरलाइनों पर प्रतिबंध की चेतावनी दी है, और साथ ही चीन पर नए टैरिफ़ (शुल्क) लगाने की धमकी से वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई है।

ट्रंप ने अपने चीन विरोधी अभियान को एक नई दिशा देते हुए घोषणा की है कि रूसी हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने वाली सभी चीनी एयरलाइन्स के अमेरिका आने पर रोक लगाई जाएगी। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय विमानन जगत को गहराई से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि रूस का हवाई मार्ग एशिया और पश्चिमी देशों - विशेषकर उत्तर अमेरिका के बीच सबसे छोटा रास्ता है।

चीन ने इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि इस प्रतिबंध से सबसे अधिक प्रभावित चीन की एयरलाइंस ही होंगी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या एयर इंडिया और अन्य भारतीय एयरलाइंस भी इस अमेरिकी कदम से प्रभावित होंगी।

अमेरिका के परिवहन विभाग को कुछ समय से शिकायत है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद, रूस ने पश्चिमी देशों के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इसके परिणामस्वरूप यूरोपीय और अमेरिकी एयरलाइनों को अपने महाद्वीपीय मार्गों पर रूसी एयरस्पेस को दरकिनार करते हुए लंबे और महंगे रास्ते अपनाने पड़े। जिससे इनका लागत व टिकट दर बढ़ गई।

चीनी एयरलाइन्स ने इस स्थिति का लाभ उठाया, क्योंकि उन्हें अब भी रूसी हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने की अनुमति थी। रूस का विशाल क्षेत्र - जो पश्चिमी यूरोप से लेकर जापान के पूर्वी तट तक फैला है - वैश्विक विमानन यातायात के लिए अत्यंत रणनीतिक माना जाता है।

पिछले दो वर्षों में चीनी एयरलाइनों ने यूरोप और एशिया के बीच मुख्य मार्गों पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, जबकि अमेरिकी और यूरोपीय एयरलाइनों की हिस्सेदारी घट गई है। अब ट्रंप प्रशासन ने इस पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है।

ट्रंप ने चीन के खिलाफ एक और मोर्चा भी खोल दिया है। हाल ही में चीन ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों और मैग्नेट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं। उदाहरण के लिए, भारत को यह आश्वासन भी देना पड़ा कि चीन से आयातित दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट्स को किसी भी रूप में अमेरिका को नहीं दिया जाएगा।

इसी के जवाब में, ट्रंप ने घोषणा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अहमदाबाद की तीन फर्मों पर ईडी की रेड

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आठ और नौ अक्टूबर को अहमदाबाद में छह स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई 10.95 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है।

ईडी ने जांच की शुरुआत सीबीआई की एफआईआर के आधार पर की थी, जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में तीन फर्मों-ओम फैब, बाबा टैक्सटाइल्स और लक्ष्मी फैब-का नाम शामिल है। ये सभी फर्में रंजीत कुमार जे. लूनिया की हैं और ग्रे क्लॉथ के व्यापार में जुड़ी थीं।

- अहमदाबाद की इन तीन फर्मों के खिलाफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने 10.95 करोड़ रूपए के घोटाले की शिकायत की थी।

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिये बैंक से कैश क्रेडिट सुविधाएं हासिल कीं और स्वीकृत धनराशि का इस्तेमाल मकानों के ऋण चुकाने, अचल संपत्ति खरीदने, सोना-चांदी के बुलियन खरीदने और नकद निकासी जैसे निजी कार्यों में किया गया। जिसमें बैंक को कुल 10.95 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

रविवार को राबड़ी देवी व लालू यादव के साथ तेजस्वी दिल्ली पहुँचे

तेरह अक्टूबर को तीनों को एक मुकदमे में हाजरी दर्ज करानी है, पर, तेजस्वी के एजेंडा में राहुल गांधी से मुलाकात भी बड़ी प्राथमिकता रखती है

- तेजस्वी गठबंधन की सीटों पर राहुल का अंतिम निर्णय चाहते हैं, जो बातचीत के बाद भी फंसी हुई हैं।
- तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन की ओर से मु.मंत्री का उम्मीदवार घोषित करने का निर्णय भी अभी लटका हुआ है।
- तेजस्वी इन बातों पर राहुल का निर्णय, राहुल की प्रस्तावित रायबरेली व हरियाणा की यात्रा से पहले फाइनल करवाना चाहते हैं।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11, अक्टूबर। राजद नेता तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी के साथ कल दिल्ली पहुँचेंगे। यह यात्रा सोमवार, 13 अक्टूबर को अदालत में पेशी के सिलसिले में हो रही है।

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली प्रवास के दौरान तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से मुलाकात होने की संभावना है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे से जुड़ी कुछ विवादित सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी।

यह भी समझा जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के लिए मुख्य चेहरे के तौर पर औपचारिक रूप से कब घोषित किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। यह तय माना जा रहा है कि यह घोषणा जल्द होगी, हालांकि आज इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई, जबकि इसकी उम्मीद थी।

इस बीच, राहुल गांधी की यात्रा का कार्यक्रम भी तय है, वे रायबरेली के दौरे के बाद हरियाणा जाएंगे। हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या ने वहाँ की भाजपा सरकार को संकट में डाल दिया है, क्योंकि मृत अधिकारी द्वारा अपने सुसाइड नोट में जिन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लिखे गए थे, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

मृतक अधिकारी की पत्नी आरोपित अधिकारियों की गिरफ्तारी की माँग कर रही है, जबकि फिलहाल केवल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण किया गया है। इस मामले में सोनिया गांधी ने भी मृतक अधिकारी के प्रति सहानुभूति जताते हुए पत्र लिखा है, और अब राहुल गांधी स्वयं हरियाणा जाकर परिवार से मुलाकात करेंगे।

कांग्रेस और राजद दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस समय प्राथमिकतता महागठबंधन की एकजुटता बनाए रखना, सीट बंटवारे की सभी अड़चनों को दूर करना और उचित उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करना है, ताकि आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को मजबूत चुनौती दी जा सके।

बड़े पैमाने पर दल बदल हो रहा है बिहार में

यह स्पष्ट संकेत है, बिहार में भारी राजनैतिक अनिश्चितता है

- राजनैतिक विश्लेषकों का कहना है कि दल बदल बिहार की राजनीति में नया नहीं है, पर, इस बार बड़े पैमाने पर दल बदल इसलिए हो रहा है, क्योंकि अधिकतर नेताओं में अपने राजनैतिक भविष्य को लेकर भारी आशंकाएं हैं, इसलिए टिकट नहीं मिलने की संभावना भांपकर भी कई नेता दल बदल कर रहे हैं।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11, अक्टूबर। जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति में अभूतपूर्व उथल-पुथल देखी जा रही है। सत्तारूढ़ नैशनल डैमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन दोनों रविवार शाम तक अपने अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तैयारी में हैं। इसी बीच टिकट की दौड़ में असंतुष्ट नेता बड़ी संख्या में दल बदल कर रहे हैं और बेहतर संभावनाओं की तलाश में अपनी मूल पार्टियों को छोड़ रहे हैं।

हालाँकि अभी तक किसी दल ने औपचारिक नामांकन दाखिल नहीं किया है, लेकिन ''निर्वाचन आयोग'' ने शुक्रवार को 121 सीटों के लिए पहले चरण के नामांकन शुरू कर दिए हैं, जबकि दूसरे चरण के नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होंगे।

बिहार की राजनीतिक संस्कृति में दलबदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसका पैमाना और रफ़्तार असामान्य रूप से तेज़ है। दर्जनों पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और यहाँ तक कि मौजूदा विधायक भी अपने दलों को छोड़कर दूसरे खेमों में शामिल हो रहे हैं, कभी टिकट वितरण में असंतोष के कारण, तो कभी आंतरिक गुटबाज़ी या राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश में।

एक प्रमुख उदाहरण में, संतोष कुशवाहा, जो पूर्णिया से जद (यू) के पूर्व सांसद हैं, टिकट न मिलने पर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। अजय कुमार निषाद, जो मुज़फ्फरपुर से भाजपा के दो बार के सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार टिकट न मिलने पर कांग्रेस में चले गए थे, अब वापस भाजपा में लौट आए हैं। निषाद की वापसी यह दर्शाती है कि इस चुनावी माहौल में राजनीतिक निष्ठाएँ कितनी लचीली हो चुकी हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, टिकट वितरण की प्रक्रिया ने लगभग सभी दलों में असंतोष फैला दिया है। कई पुराने कार्यकर्ता और स्थानीय नेता शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें नज़रअंदाज़ कर नए चेहरों या धनबल वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जा रही है।

आरजेडी-कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन में भी बगावत की स्थिति बनी हुई है। कुछ असंतुष्ट प्रत्याशी छोटे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए की बैठकें बेनतीजा

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) दलों के बीच शनिवार को पूरे दिन चली बैठकें देर शाम तक बेनतीजा रही।

- भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जीतन राम मांझी व उपेन्द्र कुशवाहा से अलग-अलग लम्बी बैठकें की थी पर नतीजा नहीं निकला।

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने राजग गठबंधन में सीट बंटवारे की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दी है। भाजपा राजग के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे के लिए सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है लेकिन सभी दल अधिक सीट मांग रहे हैं जिसके कारण इसको लेकर अंतिम राय नहीं बन सकी है।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर दिन में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सभी बोइंग 787 वायुयानों को ग्राउण्ड करें, जाँच-पड़ताल के लिए'

फैडरेशन ऑफ इण्डियन पायलट्स ने कहा कि उड्डयन तकनीकी मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं है

- फैडरेशन ने गत दिनों में ही दो घटनाओं में, फ्लाइट एआई-117 और एआई-154 में बाल-बाल बचने का विवरण दिया।
- इसी संदर्भ में फैडरेशन ने कहा, अहमदाबाद में हुए एआई-171 क्रैश के बाद इन दो संभावित दुर्घटनाओं का मतलब है कि मैन्टेनैन्स प्रणाली में दोष है। ये दुर्घटनाएं आकस्मिक दुर्भाग्य के कारण नहीं हुई हैं।
- अति आधुनिक बोइंग 787 वायुयान में इलैक्ट्रिकल सिस्टम में थोड़ी सी त्रुटि होना घातक साबित होता है। अतः सभी 787 विमानों को ग्राउण्ड करके गहराई से तकनीकी जाँच करनी चाहिए जिससे जाना जा सके कि त्रुटि कहाँ है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11, अक्टूबर। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों पर एक बार फिर सवाल उठे हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफ.आई.पी.) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से तुरंत इन विमानों को ग्राउंड (उड़ान रोकने) करने की मांग की है। यह चेतावनी लगातार सामने आ रही तकनीकी खराबियों और डी.जी.सी.ए. (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) की विशेष ऑडिट रिपोर्ट के बाद आई है, जिससे रखरखाव में लापरवाही और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर आशंकाएँ पैदा हुई हैं।

10 अक्टूबर 2025 को जारी एक कड़े शब्दों वाले पत्र में, एफ.आई.पी. के अध्यक्ष कैप्टन सी.एस. रंधावा ने एक ही हफ्ते में हुई दो गंभीर घटनाओं, एआई-117 और एआई-154 का हवाला दिया। उन्होंने लिखा, ''देश में बी-787 विमानों में हो रही खराबियों की जांच न करने से हवाई यात्रा की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बार-बार होने वाली ये खराबियाँ किसी एक तकनीकी समस्या का परिणाम नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में खामी का संकेत हैं।

पायलट संघ ने चेतावनी दी कि एआई-171 हादसे के बाद ये नई खराबियाँ एयर इंडिया के रखरखाव तंत्र में गहरे स्तर की समस्याओं को उजागर करती हैं, खासकर तब से, जब एयरलाइन ने रखरखाव की जिम्मेदारी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (ए.आई ई.एस.एल.) से लेकर नए भर्ती किए गए इंजीनियरों को सौंप दी। पत्र में कहा गया, ''बार-बार आने वाली तकनीकी खराबियां प्रशिक्षण, अनुभव और निगरानी में कमियों को दर्श्राती हैं यह मामूली बात नहीं है, ये यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को सीधे खतरे में डालती हैं।''

बोइंग 787 जैसे बड़े विमान में विद्युत प्रणाली की खराबी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ये नेविगेशन, उड़ान नियंत्रण और ऑनबोर्ड निगरानी प्रणालियों को प्रभावित कर सकती हैं। एक इन्डिपैन्डैंट एविएशन सेफ्टी एनालिस्ट मीरा जोशी ने कहा, ''एक छोटा-सा विद्युत दोष भी उड़ान के दौरान गंभीर आपात स्थिति में बदल सकता है। नियमित जाँच और रखरखाव के सख्त नियमों का पालन ही यात्रियों की सुरक्षा का एकमात्र तरीका है।''

एफ.आई.पी. ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से तात्कालिक कदम उठाने की सिफारिश की है:

बोइंग 787 विमानों को तब तक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैनडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद आज भारत में

नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर। भारत और कनाड़ा के संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कवायद के बीच कनाड़ा की विदेश मंत्री अनिता आनंद रविवार शाम तीन दिन की भारत यात्रा पर यहां पहुंचेंगी। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अनिता आनंद सोमवार दोपहर को विदेश मंत्री डा.एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगी।

- वे तीन दिन की यात्रा पर भारत आ रही हैं। यात्रा का लक्ष्य दोनों देशों के संबंध मजबूत बनाना है।

बाद में शाम को वह वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मिलेंगी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से परस्पर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी।

नोबेल प्राइज़ विजेता युगल डुफलो और अभिजीत बनर्जी एमआईटी छोड़ेंगे और युनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख जायेंगे

युनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख के प्रैसिडैंट माइकल शैपमैन ने कहा, हम गौरवान्वित हैं कि विश्व में इस समय सबसे प्रतिष्ठित व प्रभावशाली इकॉनमिस्ट हमारी युनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं

- यह हमारी युनिवर्सिटी के लिए वाकई में एक क्वांटम छलांग है।
- एमआईटी इस प्रकार अमेरिका की पहली प्रीमियम युनिवर्सिटी है, जिसने ट्रंप की सरकार की फंडिंग को अस्वीकार कर दिया है।
- इस लब्ध प्रतिष्ठित इकोनॉमिक युगल को विदेशी युनिवर्सिटी से जुड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी तथा एमआईटी में पार्ट टाइम पोज़ीशन बरकरार रखने की इजाज़त भी दी है, जिससे उनके रिसर्च प्रोजैक्ट एमआईटी में जारी रहें।
- एमआईटी की प्रैसिडैंट सैली कॉर्नब्लूथ ने इस मौके पर कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा भेजे गये शर्त दस्तावेज उन्हें स्वीकार नहीं हैं, क्योंकि एमआईटी के सिद्धांतों के अनुसार, साइंटिफिक फंडिंग का निर्णय साइंटिफिक मैरिट ही होना चाहिए और कुछ नहीं।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के विश्वविद्यालयों पर जारी हमलों के बीच, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एस्टर डूफलो और अभिजीत बनर्जी अगले वर्ष मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) छोड़कर अगले वर्ष तक स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ़ ज्यूरिक (यूज़ैडएच) जॉइन कर लेंगे।

यह कदम अमेरिका का नुकसान और स्विट्ज़रलैंड का लाभ साबित होगा। क्योंकि ये दोनों प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ज़्यूरिक युनिवर्सिटी में डवलपमेन्ट इकॉनॉमिक्स के लिए एक नया केन्द्र स्थापित कर सकते हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब अमेरिकी विश्वविद्यालय वाइट हाउस से संघीय अनुसंधान फंडिंग पर लगाई जा रही नई शर्तों को लेकर टकराव की स्थिति में हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख ने शुक्रवार को घोषणा की कि ये दम्पति जिन्हें 2019 में, माइकल क्रेमर के साथ, ''अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी कम करने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोण'' के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे एक जुलाई 2026 से विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में ''लेमन फाउंडेशन प्रोफेसर ऑफ इकॉनॉमिक्स'' के रूप में शामिल होंगे।

फ्लोरियन शॉयर, जो यूबीएस प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं, ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ''मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नोबेल विजेता एस्टर डूफलो और अभिजीत बनर्जी 1 जुलाई 2026 से ज्यूरिख विश्वविद्यालय के हमारे अर्थशास्त्र विभाग में लेमन फाउंडेशन प्रोफेसर के रूप में शामिल होंगे। यह हमारी युनिवर्सिटी के लिए क्वांटम छलाँग होगी।''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में ओवैसी 32 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे

किशनगंज,11 अक्टूबर। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की व कहा कि उनकी पार्टी बिहार के 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी।

- ये बत्तीस सीटे सोलह जिलों में हैं।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उनकी पार्टी किशनगंज की चार सीटों केअलावा , पूर्णिया की तीन, कटिहार की पांच, अररिया की दो, गया की दो, पूर्वी चंपारण की दो, नवादा की एक, जमुई की एक, भागलपुर की दो, सिवान की एक, दरभंगा की चार, समस्तीपुर की एक, सीतामढ़ी की एक, मधुबनी की एक, बैशाली की एक और गोपालगंज की एक सीट से चुनाव लड़ने जा रही है।